भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4105

दिनांक 25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

टैरिफ प्रतिबंध

4105, श्री कल्याण बनर्जी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को व्यापार प्रतिबंधों पर अमेरिकी टैरिफ पारस्परिकता के भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी है जिसमें पांच प्रतिशत से अधिक की गिरावट हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो घरेलू उद्योगों विशेषकर एमएसएमई पर उच्च टैरिफ दरों के दीर्घकालिक प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारत के बाजार को कम कीमत वाले अमेरिकी आयातों से बचाने के लिए कोई प्रस्ताव रखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय निर्यातकों और आयातकों के बीच, विशेषकर आईटी, फार्मा बनाम खनिज ईंधन, प्रसंस्कृत खाद्य और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में समतुल्य लाभ सुनिश्चित करने के लिए कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ.) अमेरिका ने दिनांक 13 फरवरी, 2025 को पारस्परिक व्यापार और प्रशुल्क संबंधी ज्ञापन जारी किया जिसमें वाणिज्य सचिव और संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि व्यापारिक भागीदारों द्वारा अपनाई गई किसी भी गैर-पारस्परिक व्यापार व्यवस्था से अमेरिका को हानि की जांच करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे और प्रत्येक व्यापारिक भागीदार के लिए विस्तृत प्रस्तावित उपायों के साथ एक रिपोर्ट प्रदान करेंगे, जिसके आधार पर संबंधित व्यापारिक भागीदार के विरुद्ध अमेरीका द्वारा कार्रवाई किसी प्रासंगिक अमेरीकी कानूनों के अंतर्गत की जा सके । वर्तमान तिथि तक अमेरीका द्वारा भारत पर पारस्परिक टैरिफ सहित कोई देश विशिष्ट अधिरोपण नहीं है। अमेरिका द्वारा सभी देशों से बिना किसी छूट के इस्पात और एल्युमीनियम आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। इन शुल्कों, जो मौजूदा ऐसे अतिरिक्त शुल्कों के ऊपर वृद्धि है, का गहन

मूल्यांकन इस तथ्य के कारण किया जा रहा है कि इन क्षेत्रों में कुछ प्रमुख निर्यातक देशों को पहले दी गई छूटों की तुलना में कोई छूट नहीं दी गई है।

भारत सरकार परस्पर लाभकारी एवं निष्पक्ष तरीके से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने एवं व्यापक बनाने के लिए अमरीकी सरकार के साथ निरंतर नियोजित है। दोनों देशों ने दिनांक 13 फरवरी, 2025 को एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें आर्थिक संबंधों को गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। महत्वाकांक्षी "मिशन 500" के तहत, दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक अमेरिका-भारत व्यापार को दोगुना से अधिक 500 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचाना है, जिसे कई क्षेत्रों में व्यापार संबंधों को गहरा करके हासिल किया जा सकता है। दोनों देश की पारस्परिक रूप से लाभदायक, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने की योजना है। दोनों देश बाजार पहुंच बढ़ाने, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने, आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को बढ़ाने और द्विपक्षीय व्यापार संबंधी मुद्दों का हल करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

*****